दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

जनवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **5**

- नीरू सिंह ज्ञानी एमडीएल में निदेशक मनोनीत 5
- 'अडॉप्ट एन आँगनवाड़ी-कार्यक्रम 5
- प्रदेशव्यापी नि:शुल्क ब्रुसेला टीकाकरण अभियान 6
- मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 6
- 'जीआईएस सर्वे ऐप' 7
- स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने की शैक्षणिक मेले की शुरुआत 7
- राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार 8
- जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास संस्थान का एप्को में विलय 8
- मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम, 2021 9
- सनावद में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का हुआ भूमि-पूजन 9
- राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया 9
- युवा दिवस पर हर ज़िले में रोज़गार मेला 10

नोट :

- पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में पुरस्कार वितरण 10
- ग्रेडिंग के आधार पर प्रदेश की पंचायतें होंगी पुरस्कृत 11
- रोइंग अकादमी को राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मिले 7 पदक 11
- 'आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें' 12
- ट्राइबल म्यूजियम को विश्व-स्तरीय बनाने की घोषणा 12
- केशव पांडे 'दखल गौरव सम्मान-2022' से सम्मानित 13
- मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन और उपचार प्रबंधन में अन्य राज्यों से आगे 13
- बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर 14
- भोपाल के नेशनल अस्पताल में विश्व की आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन 14
- प्रदेश के दो नेशनल पार्क में एयर सफारी 14
- उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र के लिये बना अति उच्च दाब सब-स्टेशन बरगी हुआ ऊर्जीकृत 15
- घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी 15
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 16
- राज्य मंत्रिपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 का अनुमोदन किया 17
- जेल विभाग के कर्मचारियों को उच्चतर रिक्त पद पर मिलेगी पदस्थापना 18
- 'जल महोत्सव' को स्पेन में मिला भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 18

नोट :

- राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल गठित 19
- अंडमान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शहीद स्मृति में नए तीर्थ का उदय 19
- बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा 20
- सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खोल मध्य प्रदेश बना नंबर वन 21
- 25 ज़िलों में कृषि विभाग की झाँकियों को मिले पुरस्कार 21
- मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का हुआ गठन 22
- मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 22
- 'मास्क ही है ज़िंदगी' अभियान में 2 लाख 91 हज़ार 631 मास्क वितरित 23
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में धारा 44 लागू 24
- मध्य प्रदेश में बनेगा भारत का पहला जियो पार्क 24
- 'बीटिंग द रिट्रीट' के साथ संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह 24
- फरवरी को 'स्वच्छता संकल्प माह' के रूप में मनाया जाएगा 25

नोट :

मध्य प्रदेश

नीरू सिंह ज्ञानी एमडीएल में निदेशक मनोनीत

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश ग्वालियर की नीरू सिंह ज्ञानी को मजगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में निदेशक मनोनीत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एमडीएल में नीरू सिंह ज्ञानी के साथ हैदराबाद मल्लिकार्जुन राव और गुजरात के संभू प्रसाद तुंडिया को भी नियुक्त किया गया है।
- गौरतलब है कि एमडीएल कंपनी भारत सरकार सुरक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है, जो समुद्री जहाज और पनडुब्बी का निर्माण करता है।
- वर्तमान में नीरू सिंह ज्ञानी पंजाबी साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की निदेशक के रूप में कार्यरत है। निदेशक के साथ वे एमडीएल का कार्य भी देखेंगी।
- उन्होंने मुंबई स्थित एमडीएल कार्यालय पहुँचकर अपना पदभार सँभाला और प्रथम निदेशक के रूप में बैठक में हिस्सा लिया। वे (एमडीएल) द्वारा आयोजित निदेशक मंडलों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेंगे। उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिये रहेगा।

'अडॉप्ट एन आँगनवाड़ी-कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश में आँगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिये समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 'अडॉप्ट एन आँगनवाड़ी 'कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में आँगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिये जन-प्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर-शासकीय संस्थाएँ, औद्योगिक संस्थाएँ और अन्य संगठन अधो-संरचना, आँगनवाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं।
- आँगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिये आँगनवाड़ी भवन एवं परिसर के लिये भूमि, आँगनवाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण, पूर्व से निर्मित भवनों का सुधार, रंग-रोगन, पूर्व से निर्मित भवनों की बाउंड्री-वॉल का निर्माण, केंद्र में हैंड-पंप की स्थापना, बच्चों के लिये सुलभ शौचालय आदि के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त आँगनवाड़ी संचालन में सहयोग के लिये आउटडोर एवं इंडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना तथा केंद्र के संचालन में आवश्यक सामग्री जैसे पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन आदि उपलब्ध करा सकते हैं।
- साथ ही जन-प्रतिनिधि बच्चों के पोषण सुधार के लिये आवश्यक वित्तीय अथवा पोषण सामग्री का प्रदाय, अति कम वज़न वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजने के लिये आवश्यक सहयोग तथा उनके परिवार को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग अथवा सामग्री के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- आँगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिये ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर को सहयोग राशि प्रदान की जा सकेगी। राशि, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी।

नोट :

प्रदेशव्यापी नि:शुल्क ब्रुसेला टीकाकरण अभियान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों को ब्रुसेला टीकाकरण अभियान में 4 से 8 माह की गौ-भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि ब्रुसिलोसिस बीमारी की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2022 तक नि:शुल्क ब्रुसेला टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालकों से अभियान का भरपूर लाभ उठाने की अपील करते हुए मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि ब्रुसिलोसिस रोग गौ-भैंस वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी है, जो ब्रुसिलोसिस एबॉर्टस जीवाणु के कारण होती है।
- इस रोग के लक्षणों में बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बाँझपन, हीट में देरी, लेक्टेशन में बाधा आदि से बछियों की हानि और दूध के उत्पादन में कमी होती है।
- मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि 4 से 8 माह की उम्र की गौ-भैंस वंशीय बछियों का जीवन-काल में एक बार टीकाकरण कर उन्हें ब्रुसिलोसिस रोग से बचाया जा सकता है।
- मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अपने क्षेत्र की उत्त आयु वर्ग में आने वाली सभी गौ-भैंस वंशीय बछियों का ब्रुसेला टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। टीकाकरण से न केवल गाय, भैंस स्वस्थ रहेंगी, दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 4 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद के बैठक में 'आनंद विभाग'का गठन एवं 'अध्यात्म विभाग'का नाम परिवर्तित कर 'धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग'करने के लिये कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग- लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस (स्टार्स) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। स्टार्स भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसे 6 राज्यों- मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल में स्वीकृत किया गया है।
- स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और शासन-विधि (गवर्नेंस) का सुधार है। स्टार्स परियोजना में ऐसी गतिविधियाँ तथा नवाचार प्रस्तावित हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान में प्रावधानित नहीं किये जा सकते हैं। स्टार्स परियोजना में सबके लिये शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण (होल स्कूल अप्रोच) शामिल रहेंगे।
- मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी में अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में 1660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई, जिसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश पॉवर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एस.ई.सी.एल के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, के लिये नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
- प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 4665 करोड़ 87 लाख रुपए है। परियोजना के लिये राज्य शासन द्वारा 15 प्रतिशत राशि अंशपूंजी के माध्यम से दी जाएगी।
- योजना में उपार्जन कार्य में संलग्न राज्य की विभिन्न एजेंसियों की हानि तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में मापदंड नियत करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें खाद्य, सहकारिता, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

नोट :

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य मुख्यत: पशु नस्ल विकास, रोज़गार सृजन, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, अनुसंधान कर मैदानी स्तर पर लाना तथा उद्यमिता विकास करना है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन में उक्त गतिविधियों को शामिल कर तीन उप मिशन बनाए गए हैं। पहला पशुधन एवं कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप मिशन, दूसरा चरी-चारा विकास उप मिशन और तीसरा इनोवेशन तथा विस्तार उप मिशन है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के क्रियान्वयन से राज्य में पशुओं की नस्ल में सुधार होगा। पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी। नवीन तकनीक विकसित होकर ज़मीनी स्तर पर पहुँचेगी। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

'जीआईएस सर्वे ऐप'

चर्चा में क्यों ?

- 4 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने तथा सर्वे के कार्य के लिये 'जीआईएस सर्वे' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस मोबाइल ऐप को प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में लागू किया गया है। इस ऐप के निर्माण से उपभोक्ताओं के लाइन विस्तार संबंधी आवेदनों के निराकरण में गति आएगी तथा एस्टीमेट एवं सर्वे कार्यों को सटीक तथा पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
- 'जीआईएस सर्वे'मोबाइल ऐप से एस्टिमेट एवं सर्वे का कार्य करने के लिये मोबाइल ऐप को संबंधित स्थान पर ले जाकर ही जानकारी दर्ज की जा सकेगी। दर्ज हुई जानकारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, इसलिये इस ऐप से की गई कार्यों की गणना सटीक एवं त्रुटिहीन प्राप्त होगी।
- कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (कार्य) वी. के. जैन ने फील्ड में जाकर मोबाइल ऐप की कार्य प्रणाली का अधिकारियों के साथ परीक्षण किया तथा ऐप की विश्वसनीयता को परखा। सभी परीक्षणों में सफल होने के उपरांत ही 'जीआईएस सर्वे ऐप'को लागू किया गया है।
- 'जीआईएस सर्वे ऐप'में दर्ज जानकारी उच्चाधिकारियों को तत्काल दिखाई देगी। इससे संबंधित प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं होगा।

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने की शैक्षणिक मेले की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तुलसीनगर में शैक्षणिक मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के प्रदेशव्यापी कोविड टीकाकरण में प्रथम डोज लगवाने वाली छात्राओं को प्रमाण-पत्र दिये। साथ ही वैक्सीनेशन के लिये विद्यालय की टीम के सदस्यों को भी प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।
- मेले में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विज्ञान, गणित, आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट और वाणिज्य से संबंधित सभी प्रकार के 150 मॉडल रखे गए हैं।
- मेले में विज्ञान नाटिका एवं 'जादू नहीं विज्ञान' का आयोजन भी किया गया। विद्यालय में मॉडल के तौर पर आए हुए कोरोना वायरस, मास्क, मोटू-पतलू के कार्टूनों ने विद्यार्थियों को आकर्षित किया।

नोट :

राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को हैंडलूम एक्स-पो भोपाल हाट बाज़ार में आयोजित कार्यक्रम में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रदेश के 15 शिल्पियों को राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- आयुक्त हथकरघा एवं रेशम सुरभि गुप्ता तथा संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम घ्की प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने प्रदेश के प्रसिद्ध बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों को वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिये इन पुरस्कारों से सम्मानित किया।
- आयुक्त सुरभि गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुनकरों की कला का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कबीर और विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्यस्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को एक लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हज़ार रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 25 हज़ार रुपए की राशि, शॉल और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।
- कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिये प्रथम पुरस्कार घासीराम लालमणी (चंदेरी) को, द्वितीय पुरस्कार विकास बण्डे (महेश्वर) को तथा तृतीय पुरस्कार अनिल मुकाती (महेश्वर) को मिला।
- वहीं कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिये प्रथम पुरस्कार रूबीना बी खान (महेश्वर) को, द्वितीय पुरस्कार रेखाबाई कोली (चंदेरी) को और तृतीय पुरस्कार पन्नालाल खरे (महेश्वर) को प्राप्त हुआ।
- राज्यस्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिये प्रथम पुरस्कार (संयुक्त) सुगंधा जैन (इंदौर) एवं मो. काजिम खत्री (धार) को, द्वितीय पुरस्कार (संयुक्त) मो. मोहसीन छीपा (उज्जैन) एवं सुभाष पोयाम (भोपाल) को, तृतीय पुरस्कार (संयुक्त) बलदेव बागमारे (बैतूल) डॉ. राजीव नाफड़े (होशंगाबाद) को मिला।
- वहीं प्रोत्साहन पुरस्कार हयात गुट्टी (उज्जैन), मो. आसिफ (उज्जैन) एवं अब्दुल करीम खत्री (धार) को प्रदान किये गए।

जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास संस्थान का एप्को में विलय

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट (जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास संस्थान) का विलय पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास संस्थान (सीसीसी एंड एसडी) की वार्षिक सभा की बैठक में इसका विघटन एप्को में करने का निर्णय लिया गया था।
- राज्य शासन द्वारा पर्यावरण विभाग में वर्ष 2009 में सीडीएम एजेंसी का गठन सोसायटी अधिनियम में किया गया था। इसके बाद सीडीएम एजेंसी का नाम परिवर्तित कर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया।
- राज्य शासन द्वारा एप्को में राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना कर एप्को को राज्य डेजिग्नेटेड एजेंसी का दायित्व सौंपा गया।
- इस ज्ञान केंद्र की गतिविधियों और मानव संसाधन के लिये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान मिशन के तहत अनुदान दिया जाता है।

नोट :

मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम, 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय इस अधिनियम को 3 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई।
- उन्होंने कहा कि आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों (सांप्रदायिक या अन्यथा), लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- विधि मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने में संलिप्त रहने वाले लोगों से कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिये दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानित है।

सनावद में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का हुआ भूमि-पूजन

चर्चा में क्यों ?

- 6 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने खरगोन जिले के सनावद में 9 करोड़ 68 लाख 83 हजार रुपए की लागत से बनने वाले एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का भूमि-पूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस क्लस्टर के निर्माण में भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा चार करोड़ 68 लाख रुपए प्रदान किये जा रहे हैं।
- भारत सरकार द्वारा देश में निर्मित किये जा रहे 13 नए क्लस्टरों में से सनावद का क्लस्टर भी शामिल है। इसके निर्मित हो जाने से क्षेत्र में कई उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएँ हैं। इससे क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा।
- कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खरगोन जिले के काटकूट क्षेत्र के 80 गाँवों के किसानों को लाभांवित करने के लिये शीघ्र ही 2 हजार 863 करोड़ रुपए की सिंचाई उद्वहन योजना का भूमि-पूजन किया जाएगा।
- एमएसएमई मंत्री सकलेचा ने कहा कि खरगोन क्षेत्र में कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके विकसित होने से क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। कपास के उत्पादन के बाद टेक्सटाइल मिलों में कपड़े का उत्पादन होगा।
- राज्य सरकार द्वारा उद्योग लगाने के लिये करोड़ों रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। एक करोड़ रुपए तक के उद्योग लगाने पर 40% और दस करोड़ रुपए के उद्योग के लिये 50% अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

- 7 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का राजभवन में लोकार्पण किया। वेबसाइट उन्नत तकनीकी के साथ GIGW एवं WCAG 2.0 के मापदंडों की प्रणाली के अनुरूप विकसित की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रणाली के आधार पर अभ्यर्थियों को सुगमता से सूचनाओं की प्राप्ति हो सकेगी। अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित समस्त जानकारी एवं सूचनाएँ नवीन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
- राज्यपाल ने नवीन वेबसाइट के लोकार्पण अवसर पर आयोग की गरिमा के अनुरूप पारदर्शिता और कार्य तत्परता की दिशा में किये जा रहे नवाचारों की सराहना की।
- उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस नवीन वेबसाइट के माध्यम से प्रतिभागी को समुचित जानकारियाँ सुगमता और शीघ्रता से प्राप्त होंगी। साथ ही आयोग की पारदर्शी कार्य-प्रणाली और अधिक मज़बूत होगी।

युवा दिवस पर हर ज़िले में रोज़गार मेला

चर्चा में क्यों ?

- 7 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के एमएसएमई सचिव पी. नरहरि ने बताया कि राज्य शासन 12 जनवरी को युवा दिवस पर प्रदेश के सभी ज़िलों में रोज़गार मेला लगाकर बड़ी संख्या में युवाओं को स्व-रोज़गार देगा।

प्रमुख बिंदु

- सचिव पी. नरहरि ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्व-रोज़गार की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न विभागों एवं बैंकों के माध्यम से कई स्व-रोज़गार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि प्रमुख योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
- सचिव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा स्व-रोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिये महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' प्रारंभ की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
- इसी उद्देश्य से 12 जनवरी, 2022 को प्रदेशव्यापी स्व-रोज़गार, रोज़गार दिवस मनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इसमें सभी ज़िला मुख्यालयों पर ज़िलास्तरीय कार्यक्रम तथा एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा।
- राज्य एवं ज़िला स्तर के कार्यक्रमों में लाभार्थियों को स्वीकृति वितरण-पत्र दिये जाएंगे। पूर्व से स्व-रोज़गार में स्थापित अनुभवी लोगों से स्व-रोज़गार के इच्छुक व्यक्तियों का परिचय करवाया जाएगा, जिससे उनके अनुभवों का लाभ युवाओं को मिल सके। साथ ही, स्व- रोज़गार योजनाओं के लाभान्वित सफल एवं स्थापित हितग्राहियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी, स्व-रोज़गार योजनांतर्गत स्व-नियोजन के संबंध में विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले युवाओं को परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
- मेले में विभिन्न विभागों, बैंकिंग संस्थाओं इत्यादि के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ युवा वर्ग को रोज़गार योजनाओं, स्व-रोज़गार की संभावनाओं, बैंकिंग सुविधाओं आदि की जानकारी मिलेगी।

पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में पुरस्कार वितरण

चर्चा में क्यों ?

- 7 जनवरी, 2022 को पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल में संसदीय प्रश्न-मंच प्रतियोगिता के प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय विद्यापीठ की संचालक डॉ. प्रतिमा यादव ने बताया कि विद्यापीठ द्वारा भोपाल में पहली बार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य संसदीय प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

नोट :

- आयोजन में 17 विद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया। इनमें 5 टीमों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में संसदीय विषय से संबंधित रेपिड फायर, बजर राउंड, पासिंग राउंड, ऑडियो-वीडियो राउंड और सरप्राइज राउंड के माध्यम से प्रश्न पूछे गए।
- प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सरस्वती बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, द्वितीय पुरस्कार देहली पब्लिक स्कूल और तृतीय पुरस्कार संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल के विद्यार्थियों ने प्राप्त किया।

ग्रेडिंग के आधार पर प्रदेश की पंचायतें होंगी पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

- 10 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्यों की ग्रेडिंग की जाएगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर 'स्मार्ट विलेज' बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने विभाग द्वारा गाँव-गाँव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिये बनाए गए 'मोबाइल एप' का लोकार्पण भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 127 'दीदी कैफे' स्वल्पाहार केंद्रों के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि स्थानों पर भी 'दीदी कैफे' खोले जाएंगे।
- प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 9 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सभी 45 हजार गाँवों में ग्राम संगठन बनाने के निर्देश दिये। वर्तमान में प्रदेश में 32 हजार 874 ग्राम संगठन हैं।
- उन्होंने कहा कि हर गाँव के इतिहास, गौरव, पहचान, संस्कृति, महापुरुषों आदि को पुन:स्थापित करने के लिये प्रत्येक गाँव में हर वर्ष 'ग्राम स्थापना दिवस' मनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी गाँवों को 'ओडीएफ-प्लस' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 1154 गाँवों को अभी तक 'ओडीएफ-प्लस' बनाया जा चुका है।

रोइंग अकादमी को राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मिले 7 पदक

चर्चा में क्यों ?

- 9 जनवरी, 2022 को आर्मी रोइंग नोड, पुणे में संपन्न हुई 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य रोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 काँस्य सहित कुल सात पदक अर्जित किये।

प्रमुख बिंदु

- अकादमी की खिलाड़ी खुशप्रीत कौर ने महिला एकल स्कल स्पर्धा में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अर्जित किया।
- रुक्मणी डांगी और ज्योति कुशवाहा की जोड़ी ने महिला कॉक्सलेस जोड़ी स्पर्धा में दो रजत पदक जीते।
- पुरुषों की कॉक्सलेस फोर स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी मेहुल कृष्णानी, अजय सिंह, रोहित सेंधव और सोहेल ने रजत पदक अर्जित किया।
- मंगल सिंह और तरुण डांगी की जोड़ी ने मेंस डबल स्कल इवेंट में काँस्य पदक जीता। मंगल सिंह और मोनिका भदौरिया की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स स्कल इवेंट में काँस्य पदक अर्जित किया।

नोट :

'आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें'

चर्चा में क्यों ?

- 11 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 'आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें'का संदेश पूरे प्रदेश में प्रसारित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा वे भी भोपाल में एक आंगनबाड़ी गोद लेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित करें। इसके साथ ही घोषणा की कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि बाल-विकास और बाल-संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण के लिये बेहतर ढंग से कार्य करें। आंगनबाड़ी सेवाएँ एवं पोषण अभियान में अच्छा कार्य हो।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 956 है, जो भारत के लिंगानुपात 929 से अधिक है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लाडली लक्ष्मी 2.0 पोर्टल का विकास एवं उन्नयन करें तथा चाइल्ड बजटिंग पर योजना बनाकर गंभीरता से कार्य हो।
- बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों का परिवारों में पुनर्वास करने की पहल हो। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये पूरी मदद करें। क्षमता के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाएँ। पढ़ाई की अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ।

ट्राइबल म्यूजियम को विश्व-स्तरीय बनाने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 11 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान घोषणा की कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्व-स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और देखें, इस तरह की व्यवस्था करें। इसी प्रकार मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वहाँ भी पर्यटकों के ठहरने का प्रस्ताव तैयार कर भेजें।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना और लेज़र-शो का कार्य प्रथम चरण में पूर्ण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना देश और दुनिया में अद्भुत होगी।
- इंदौर में लाल बाग पैलेस का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटोहॉल) की तरह विकसित करने के निर्देश भी दिये।
- मुख्यमंत्री ने शिव की प्रतिमाओं के अभिप्राय पर केंद्रित पुस्तक 'महादेव'और परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित ब्रोशर का विमोचन किया।
- बैठक में बताया गया कि 'आज़ादी का अमृत महोत्सव'के लिये भारत सरकार की वेबसाइट पर भी समानांतर रूप से मध्य प्रदेश की प्रमुख गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति पर आधारित संग्रहालयों के निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से भारिया जनजाति का छिंदवाड़ा, बैगा का डिंडोरी और सहरिया जनजाति का श्योपुर में संग्रहालय बनाया जाना अपेक्षित है।

नोट :

केशव पांडे 'दखल गौरव सम्मान-2022' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 11 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता केशव पांडेय को भोपाल के कुक्कुट भवन में आयोजित समारोह में दखल गौरव सम्मान-2022 से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों, कानून और विधायी मामलों, जेलों और संसदीय मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा पांडे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- केशव पांडे को पत्रकारिता, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये यह पुरस्कार दिया गया।
- केशव पांडे वर्तमान में स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन उद्भव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।

मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन और उपचार प्रबंधन में अन्य राज्यों से आगे

चर्चा में क्यों ?

- 13 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के मध्यम से राज्यों की कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण और उसके प्रबंधन के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में भागीदारी की।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों से चर्चा के पहले बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश किशोर वर्ग के लिये 3 जनवरी से प्रारंभ वैक्सीनेशन के कार्य में अच्छी स्थिति में है।
- मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण कार्य में पात्र किशोरों में से 72.2 प्रतिशत को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रिकॉशन डोज 1 लाख 80 हज़ार से अधिक लोगों को लगाई गई है। इस श्रेणी में लगभग 30 प्रतिशत पात्र आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य के लिये जन-भागीदारी के मॉडल का उपयोग करते हुए सभी का सहयोग लेकर 11 विशिष्ट वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किये गए हैं। अभी तक प्रदेश में 96 प्रतिशत प्रथम डोज तथा 92 प्रतिशत द्वितीय डोज के पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- इसी प्रकार 15-18 वर्ष आयु वर्ग में और गर्भवती माताओं के टीकाकरण में भारत में सर्वाधिक टीके लगाने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है।
- इसी तरह केंद्रीय राशि के व्यय में भी मध्य प्रदेश का कार्य अच्छा है। विशेष रूप से प्रदेश में कोविड से बचाव के लिये अस्पतालों में सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, एचडीयू और आईसीयू बेड, ऑक्सीजन संयंत्र, औषधियों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 437 करोड़ 17 लाख रुपए केंद्र अंश के रूप में जारी किये गए। इनमें राज्य अंश 291 करोड़ 44 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन ने जारी किये। केंद्र और राज्य का अंश सम्मिलित करते हुए कुल 728 करोड़ 61 लाख रुपए की उपलब्ध राशि के मुकाबले राज्य ने 398 करोड़ 33 लाख रुपए का व्यय किया है। व्यय प्रगति में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश प्रथम पाँच राज्यों में शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, ज़िला अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 के लिये भारत सरकार ने इस मद में 126 करोड़ 25 लाख रुपए की मंज़ूरी दी है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में बताया गया कि देश में 92 प्रतिशत लोग प्रथम डोज लगवा चुके हैं। इसी तरह लगभग 70 प्रतिशत पात्र नागरिक दूसरी डोज लगवा चुके हैं। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ किशोरों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। कुल 1 अरब 54 करोड़ 61 लाख वैक्सीन डोज लग चुकी हैं।

नोट :

बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर

चर्चा में क्यों ?

- 14 जनवरी, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़िले के ऐंती गाँव की सुरम्य पहाड़ी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि देव मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर परिसर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि यह मंदिर धार्मिक और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, इसी को दृष्टिगत रखकर मंदिर के विकास की योजना बनाई गई है।
- शनि देव मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिये शनि परिक्रमा मार्ग के साथ शनि सरोवर और शनि कुंड का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के विकास को दो हिस्सों में बाँटा गया है- एक आंतरिक और दूसरा बाहरी विकास।
- आंतरिक विकास मंदिर परिसर के भीतर अत्याधुनिक तरीके से कराया जाएगा। इसी तरह बाहरी विकास में परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें बिजली, सड़क, कनेक्टिविटी के अलावा परिक्रमा मार्ग में जन-सुविधाएँ, दुकानें और खानपान की सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न आए।
- वर्तमान में शनि मंदिर के दो परिक्रमा मार्ग हैं। एक 6 किलोमीटर दायरे में है, जबकि दूसरा परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर लंबा है। लगभग 21 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग में अन्य मंदिर भी हैं, उनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग के दोनों ओर पौधरोपण के कार्य को भी जीर्णोद्धार योजना में शामिल किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस शनि मंदिर की गिनती देश के प्राचीन शनि मंदिरों में होती है। यही नहीं इस मंदिर का धार्मिक महत्त्व भी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

भोपाल के नेशनल अस्पताल में विश्व की आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 16 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नेशनल अस्पताल में विश्व की आधुनिक और मध्य भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल अस्पताल में हृदय रोगियों के लिये यह कैथ लेब शुरू की गई है, जिससे रोगी का एकदम सही उपचार हो सकेगा। नेशनल अस्पताल इस नई कैथ लैब के मार्फत मध्य भारत में अपने सेवा-भाव से नई पहचान स्थापित करेगा।
- उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को सेवाभावी बनना चाहिये और व्यावसायिक मानसिकता से बचना चाहिये। समर्पण भाव से की गई रोगियों की सेवा से बड़ा कोई महान प्रतिफल हो ही नहीं सकता।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के लिये बड़े चिकित्सा संस्थानों को आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये सुनियोजित पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है।

प्रदेश के दो नेशनल पार्क में एयर सफारी

चर्चा में क्यों ?

- 17 जनवरी, 2022 को निजी एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी के सीईओ मनीष सैनी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के दो राष्ट्रीय उद्यानों- कान्हा और बांधवगढ़ में एयर सफारी प्रारंभ करने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री को एयर सफारी सेवा के शुभारंभ के लिये आमंत्रण भी दिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सैनी ने बताया कि पहली बार एयर सफारी की योजना क्रियान्वित होगी। इसके लिये 2 से 14 सीटर के एयर क्रॉफ्ट उपयोग में लिये जाएंगे, जिनका निर्माण भी मध्य प्रदेश में हो, इसके प्रयास किये जा रहे हैं।
- विमानन विभाग के सहयोग से आगामी दो माह में इसकी शुरुआत की योजना है। साथ ही प्रथम स्पोर्ट्स एयर क्रॉफ्ट एयर शो पर भी विचार किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि कोविड की लहर थमते ही पर्यटन की गतिविधियों का विस्तार होगा और तब बांधवगढ़ नेशनल पार्क एवं कान्हा नेशनल पार्क के भ्रमण के लिये आने वाले पर्यटक हवाई पर्यटन का आनंद भी ले सकेंगे।

उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र के लिये बना अति उच्च दाब सब-स्टेशन बरगी हुआ ऊर्जीकृत

चर्चा में क्यों ?

- 17 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि जबलपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बरगी क्षेत्र के चंदेरी ग्राम में 132 के.वी. के नए अति उच्च दाब सब-स्टेशन को ऊर्जीकृत कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस सब-स्टेशन के प्रारंभ हो जाने से जबलपुर के उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही उमरिया डुंगरिया में फेस-एक, फेस-दो और फेस-तीन के प्रस्तावित उद्योगों के लिये विद्युत की सहज उपलब्धता रहेगी।
- अब उमरिया डुंगरिया के साथ ही मानेगाँव क्षेत्र के क्रेशर, बरगी और चरगंवा क्षेत्र के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को उचित वोल्टेज में गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।
- पहले इस औद्योगिक क्षेत्र सहित बरगी एवं चरगंवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 2 फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती थी। अब बरगी सब-स्टेशन के प्रारंभ हो जाने से 6 फीडर से बिजली मिलेगी।
- कंपनी के उमरिया डुंगरिया क्षेत्र में अब दो अति उच्च दाब सब-स्टेशनों से विद्युत सप्लाई का दोहरा विकल्प उपलब्ध रहेगा- एक 220 के.वी. जबलपुर से तथा दूसरा सीधे बरगी पावर हाउस से।
- बरगी (चंदेरी) में सब-स्टेशन बनने से 33 के.वी. लाइनों की लंबाई भी कम होगी। जो पहले 40 कि.मी. थी, वो अब घटकर 12 कि.मी. की हो गई है। इससे उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज पर सप्लाई की समस्याओं से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही घने जंगल और नर्मदा क्रॉसिंग के कारण विद्युत सुधार कार्य में आसानी होगी।
- उमरिया डुंगरिया में 33 के.वी. के 2, 11 के.वी. के 6 तथा निम्न दाब के 60 उपभोक्ताओं के औद्योगिक कनेक्शन हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से फायदा तो मिलेगा ही, इसके अलावा तकरीबन 147 गाँवों के करीब 25 हज़ार 650 उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे।
- 132 के.वी. बरगी (चंदेरी) के ऊर्जीकृत होने से जबलपुर ज़िले की पारेषण क्षमता में वृद्धि हुई है। जबलपुर ज़िले में अब 220 के.वी. के 4 तथा 132 के.वी. के 9 सब-स्टेशन हो गए हैं।
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का यह प्रदेश में 404वाँ अति उच्च दाब केंद्र है। प्रदेश में इस समय ट्रांसमिशन कंपनी के 400 के.वी. के 14 सब-स्टेशन, 220 के.वी. के 84 सब-स्टेशन तथा 132 के.वी. के 306 सब-स्टेशन क्रियाशील हैं।

घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिये परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी है।
- मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान 'निरामयम' मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिह्नित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया।
- उपरोक्तानुसार इन्हें पात्र माने जाने के लिये भारत शासन को भी लिया जाएगा। जब तक भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक आयुष्मान 'निरामयम' मध्य प्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।
- आयुष्मान 'निरामयम'मध्य प्रदेश योजना की सीमा के बाहर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिये संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 24 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार यदि एक ही भूखंड का मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यावसायिक/वाणिज्यिक) है तो ऐसे भूखंड के लिये आवासीय उपयोग के अंश भाग का प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक की गणना आवासीय प्रयोजन अनुसार की जाएगी।
- इसी भूखंड पर व्यावसायिक/वाणिज्यिक अंश भाग के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दर का 120 प्रतिशत प्रीमियम तथा आवासीय प्रयोजन अनुसार वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, जहाँ एक परिवार द्वारा दो अलग-अलग भूखंडों में से एक का आवासीय और दूसरे का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किया जाना है, ऐसे प्रकरणों में दो पृथक्-पृथक् पट्टे प्रदान किये जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में परिवार को परिपत्र के अंतर्गत एक बार लाभ दिया जाना ही माना जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्थ अन्य प्रावधान किये। इसमें आयोग द्वारा प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये हितग्राहियों का चिह्नांकन, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिंदुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषंगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल हैं।
- मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सेवा के मद्देनज़र अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल हैं।
- मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर में जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पाद की निर्माण क्षमता विकसित किये जाने के दृष्टिगत मेसर्स शबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन को 07 क्यूबिक मी डी टाईप गैस सिलेंडर निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, उज्जैन में स्थित उपलब्ध भूमि में से 50 हज़ार वर्गफीट भूमि सीधे आवंटित किये जाने का निर्णय लिया।

नोट :

- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में SPV (Special Purpose Vehicle) M.P. State Assets Management Company (MPSAMC) के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया।
- मंत्रिपरिषद ने 'विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग'का नाम बदलकर 'घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग' करने का निर्णय लिया।

राज्य मंत्रिपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 का अनुमोदन किया

चर्चा में क्यों ?

- 18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है। इससे गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- नई आबकारी व्यवस्था के तहत निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं-
  - मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा।
  - सभी ज़िलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा।
  - समस्त मदिरा दुकानें कंपोजिट शॉप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियाँ नहीं बनेंगी।
  - कलेक्टर एवं ज़िलों के विधायकगण की उच्चस्तरीय ज़िला समिति को उनके ज़िले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन का अधिकार होगा।
  - प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी।
  - देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य ज़िलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी। इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी।
  - राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदिरा का ट्रैक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा।
- हेरिटेज मदिरा नीति के तहत निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं-
  - महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
  - वर्ष 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।
  - पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे।
  - सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
  - इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।
  - इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पर्यावरण, विद्युत विभागों और नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
  - मदिरा आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
  - होम बार लाइसेंस दिया जा सकेगा, जिसके लिये 50 हज़ार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्हीं को होगी, जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ रुपए हो।

नोट :

जेल विभाग के कर्मचारियों को उच्चतर रिक्त पद पर मिलेगी पदस्थापना

चर्चा में क्यों ?

- 20 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस विभाग की तरह ही जेल विभाग में भी पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर रिक्त पद पर कार्यवाहक के रूप में पदस्थापना की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर पद का प्रभार मिलने पर यूनिफॉर्म धारण कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किंतु उन्हें वेतन-भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे।
- जेल विभाग में प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक ज़िला जेल के रूप में पदस्थ करने संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।
- इसमें राजपत्रित अधिकारियों के आदेश राज्य शासन स्तर पर और अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों के आदेश महानिदेशक जेल के स्तर से जारी होंगे।
- अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि जेल-कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन अनुसार जेल-कारागार अधिनियम 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968 में संशोधन कर नियम 70 के पश्चात् 70(क) उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति संबंधी संशोधन स्थापित किया गया है।
- इसके अनुसार उच्चतर पद पर प्रभारी के रूप में कार्य करने वाला शासकीय सेवक वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। पदेन शक्तियों का प्रयोग और पदानुसार वर्दी धारण कर सकेगा।

'जल महोत्सव' को स्पेन में मिला भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 20 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम 'जल महोत्सव' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मेड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। फितूर (FITUR) द्वारा ऐरेलिबर (AireLibre) पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह पुरस्कार दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिये किया गया था। यह साहसिक पर्यटन, संस्कृति, प्रकृति, खाद्य और पेय पदार्थ, प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण में उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- प्रमुख सचिव पर्यटन और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रदर्शित 100 उत्पादों में से मध्य प्रदेश पर्यटन के वार्षिक प्रचार कार्यक्रम 'जल महोत्सव'को भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है।
- 'जल महोत्सव'खेल और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को आनंद एवं रोमांच की अनुभूति के लिये साहसिक गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है।
- 'जल महोत्सव'में साहसिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अन्य उत्साहवर्धक गतिविधियाँ, जैसे- हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, वाटर पैरासेलिंग, पैरा मोटरिंग, आइलैंड केंपिंग, स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग आदि का भी आयोजन किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखे/अद्वितीय नवीन पर्यटन उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

नोट :

राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल गठित

चर्चा में क्यों ?

- 21 जनवरी, 2022 को राज्य शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र शासन के दिशा-निर्देशानुसार गठित मंडल में अध्यक्ष कार्य परिषद मध्य प्रदेश गो-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव पशुपालन सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में विधायक, अशासकीय प्रतिनिधि और पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएँ शामिल की गई हैं।
- समिति पशुओं के प्रति क्रूरता एवं बरताव के निवारण, पशुओं के परिवहन में उपयोग, पशुओं के लिये शेड, पानी, चिकित्सा सहायता आदि के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर सुझाव देगी।
- विधायकों में सुमित्रा देवी कास्डेकर और राम दांगोरे, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और वन, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव, पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ), संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, प्रबंध संचालक पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम और भारतीय वन जीव कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि को सदस्य नामांकित किया गया है।
- अशासकीय सदस्यों में कैलाश ललवानी गोपाल गोशाला नलखेड़ा ज़िला आगर-मालवा, वैदपाल झा केदारधाम गोशाला एवं जैव कृषि अनुसंधान केंद्र केदारपुर ज़िला ग्वालियर, प्रमोद नेमा भोपाल, जितेंद्र नरोलिया इंदौर और शंकर लाल पाटीदार कामधेनु सेवा संस्थान इमलिया जिला रायसेन शामिल हैं।
- पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं में गो सेवा आश्रम देवरी ज़िला मुरैना, एनिमल क्योर एंड केयर ग्वालियर, श्री गोस्वामी रामानंद गोशाला गुना, श्री कृष्ण गोशाला सेवा आश्रम कुसमानिया ज़िला देवास, एनिमल एंड एनवायरनमेंट केयर ऑर्गनाइजेशन भोपाल, कामधेनु गोशाला भोपाल, श्री कृष्ण गोशाला एवं गो-संवर्धन समिति सिरोंज, त्रिवेणी गोशाला बैतूल, श्री दयोदय पशुधन संरक्षण समिति हरदा और जन-जागरण एजूकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसायटी मकरोनिया ज़िला सागर भी बोर्ड के सदस्य होंगे।
- इस सलाहकार मंडल के प्रमुख कार्य हैं-
  - पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों का पर्यवेक्षण एवं प्रशासन को सलाह देना।
  - पशुओं के प्रति क्रूरता या बर्ताव के संबंध में शासन को सलाह देना।
  - पशुओं के परिवहन में उपयोग होने वाले यानों की संरचना में सुधार हेतु शासन, प्रशासन या यान स्वामी को सुझाव देना।
  - पशुओं के लिये शेड, पानी, चिकित्सा सहायता हेतु निर्णय लेना।
  - पशुवध गृहों की संरचना, रख-रखाव के संबंध में शासन और स्थानीय प्राधिकरणों को आवश्यक सुझाव देना।
  - आवारा पशुओं को पकड़ते समय उन्हें यातना और दर्द से निजात दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाना।
  - असहाय, वृद्ध पशुओं और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा करने वाली संस्थाओं को पिंजरा, बल्लियाँ, आश्रय स्थल के निर्माण आदि के लिये आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराना।
  - पशु क्रूरता निवारण के क्षेत्र में कार्यरत् संस्थाओं को आवश्यक सहयोग देना।
  - पशुओं को सामान्यत: दी जाने वाली अनावश्यक यातनाओं के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना और पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देना शामिल हैं।

अंडमान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शहीद स्मृति में नए तीर्थ का उदय

चर्चा में क्यों ?

- 23 जनवरी, 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में सुभाष वार्ड और विकसित किये गए संग्रहालय को आम जनता के लिये खोल दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जिस तरह अंडमान निकोबार स्थित सेल्युलर जेल को वीर सावरकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, उसी तरह जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल को विकसित किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपयोग की गई वस्तुओं जैसे उनके वस्त्र, उन्हें पहनाई गई बेड़ियाँ, उनके हस्तलिखित पत्र और उनकी जेल यात्रा से संबंधित अभिलेख को संकलित कर एक संग्रहालय का स्वरूप दिया गया है।
- इस संग्रहालय से नागरिकों को राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की प्रेरणा मिलेगी। संग्रहालय और नेताजी के कारावास वाले कक्ष के दर्शन के लिये नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- मध्य प्रदेश सरकार की पहल से यह प्रदेश का प्रथम और देश का द्वितीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय होगा। नई दिल्ली में वर्ष 2019 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान ने वर्ष 2007 में जबलपुर जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था। इसके साथ ही यहाँ स्मारक के निर्माण और विकास की पहल भी प्रारंभ हुई थी।
- 23 जनवरी को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित प्रभात चौराहे के पास सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण, आज़ाद हिन्द फौज थीम पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास तथा नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज (फ्लाय ओवर) का लोकार्पण किया।
- लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में 105 आरओबी बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार से भी आरओबी निर्माण के लिये राशि मंजूर हुई है। एडीबी की सहायता से प्रदेश में 260 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं।

बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को संस्कृति विभाग की संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश की 6 बोलियों के कैलेंडर वर्ष 2018 एवं 2019 के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

- साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे ने बताया कि यह पुरस्कार मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी बोली में रचित रचनाओं के लिये दिये जाते हैं।
- भीली और गोंडी बोली के पुरस्कार के लिये कोई भी कृति प्रविष्टि के रूप में प्राप्त नहीं होने से शेष बची 4 बोलियों में यह पुरस्कार प्रदान किये गए हैं। साहित्यिक कृति पुरस्कार में सम्मानस्वरूप 51 हजार रुपए की राशि दी जाती है।
- साहित्यिक कृति पुरस्कारों में वर्ष 2018 के लिये मालवी में 'संत पीपा' स्मृति पुरस्कार इंदौर की हेमलता शर्मा को कृति 'मालवी डबल्यो' के लिये, निमाड़ी में 'संत सिंगाजी' स्मृति पुरस्कार बड़वानी के प्रमोद त्रिवेदी 'पुष्प' को 'तमक कइ करनुज' के लिये, बघेली में 'विश्वनाथ सिंह जूदेव' स्मृति पुरस्कार सतना के अनूप अशेष को 'बानी आदिम' के लिये, बुंदेली में 'छत्रसाल' स्मृति पुरस्कार टीकमगढ़ के दीन दयाल तिवारी को उनकी कृति 'बेताल की चौकड़िया' के लिये दिया गया है।
- इसी तरह वर्ष 2019 के लिये मालवी में 'संत पीपा' स्मृति पुरस्कार उज्जैन के सतीश दवे को उनकी कृति 'बात को बतंगड़' के लिये, निमाड़ी में 'संत सिंगाजी' स्मृति पुरस्कार खरगौन के जगदीश जोशीला को 'निमाड़ी धंधोरया' के लिये, बघेली में 'विश्वनाथ सिंह जूदेव' स्मृति पुरस्कार सीधी की डॉ. अंजनी सिंह सौरभ को कृति 'ठठरा माँ साँसि' के लिये और बुंदेली में 'छत्रसाल' स्मृति पुरस्कार दतिया के डॉ. राज गोस्वामी को उनकी रचना 'मौं ढाँकें करिया में' के लिये दिया गया है।

नोट :

सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खोल मध्य प्रदेश बना नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 'सुकन्या समृद्धि योजना' में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम है। प्रदेश ने इस योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है, जिसमें कुल 4238 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का संग्रहण हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से वर्तमान वित्त वर्ष में 5 लाख 68 हजार से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। योजना ने प्रदेश की बेटियों के सशक्तीकरण को नई दिशा दी है। अभिभावकों और बेटियों ने इस योजना को भरपूर समर्थन दिया है। बैंकों का भी सराहनीय सहयोग रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के सफलतम 7 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को अन्य पात्र बालिकाओं को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में गाँव के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध स्वावलंबी बनाने के लिये डाक विभाग 'बचत खाता खुशहाली का' अभियान प्रारंभ कर रहा है। यह एक अच्छी पहल है, जिसमें सभी जिले वित्तीय समावेशन को नई दिशा दे सकते हैं।
- बालिकाओं के सुकन्या खातों के साथ बालकों के लिये पीपीएफ खाता भी खोलने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी।

25 ज़िलों में कृषि विभाग की झाँकियों को मिले पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित ज़िलास्तरीय समारोह में किसान कल्याण तथा कृषि विकास की झाँकियाँ 25 ज़िलों में पुरस्कृत हुई। 6 ज़िलों में कृषि विभाग की झाँकियों को प्रथम पुरस्कार, 9-9 ज़िलों में द्वितीय और तृतीय पुरस्कार तथा एक ज़िले में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ज़िला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ज़िलों में निकाली गई झाँकियों में कृषि विभाग होशंगाबाद को 'आत्मनिर्भर भारत में कृषि का योगदान', छिंदवाड़ा को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', झाबुआ को 'प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश', सीहोर को 'जन-भागीदारी' तथा विदिशा और हरदा को 'प्राकृतिक खेती' की थीम पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- प्रदेश के 9 ज़िलों में कृषि विभाग की झाँकियों को ज़िला प्रशासन द्वारा द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। मुरैना को 'उन्नत खेती-खुशहाल किसान' और खरगौन, राजगढ़, श्योपुर, नीमच, शिवपुरी, धार, देवास तथा उमरिया को 'प्राकृतिक खेती' की थीम पर पुरस्कृत किया गया है।
- प्रदेश में कृषि विभाग की झाँकियों को 9 ज़िलों में ज़िला प्रशासन द्वारा तृतीय पुरस्कार मिला है। अनूपपुर को 'प्राकृतिक खेती एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश', सिवनी को 'जीराशंकर चावल और प्राकृतिक खेती', टीकमगढ़ को 'फसल विविधीकरण', दमोह को 'मृदा एवं जल संरक्षण', ग्वालियर को 'प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान' और बालाघाट, भिंड, खंडवा तथा रतलाम की झाँकियों को 'प्राकृतिक खेती' की थीम पर पुरस्कृत किया गया है।
- इसके साथ ही मंदसौर ज़िले के कृषि विभाग की झाँकी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है।

नोट :

मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का हुआ गठन

चर्चा में क्यों ?

- 27 जनवरी, 2022 को राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए निर्णय के पालन में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एस.पी.वी. का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी तथा प्रस्तावित एस.पी.वी. की अधिकृत शेयर पूंजी `1000 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी `10 करोड़ रखा जाना प्रस्तावित है। एस.पी.वी. के गठन के उपरांत शेयर पूंजी का 100% अंशदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का प्रशासकीय विभाग मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग होगा। कंपनी के संचालक मंडल का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
- मंडल के सदस्यों में वित्त, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, लोक निर्माण, राजस्व, वाणिज्यिक कर और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रंबधन कंपनी को सदस्य सचिव बनाया गया है।
- राज्य शासन ने संचालक मंडल के दायित्व भी निर्धारित किये हैं। इसके साथ ही कंपनी के लिये कार्यपालिक समिति का गठन कर उसके भी दायित्व निर्धारित किये गए हैं। राज्य शासन ने कंपनी के लिये वित्तपोषण की व्यवस्था, पदीय संरचना के साथ वार्षिक व्यय भी तय किया है।
- मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एस.पी.वी.के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित किये गए हैं-
  - लोक परिसंपत्तियों के युक्तियुक्त प्रबंधन के संबंध में नीति एवं दिशा-निर्देशों को तैयार करना।
  - अंतर्विभागीय विमर्श एवं समन्वय के माध्यम से राज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम की परिसंपत्तियों का युक्तियुक्तकरण कर समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
  - शासन एवं सार्वजनिक उपक्रम की संपत्तियों के मौद्रीकरण तथा प्रबंधन के लिये विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना।
  - अनुपयोगी परिसंपत्तियों के लिये प्रबंधन एवं मौद्रीकरण हेतु आवश्यक कौशल एवं योग्यतायुक्त मानव संसाधन तैयार करना।
  - सूचना प्रौद्योगिकी एवं भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से राज्य की नर्वर्तन योग्य परिसंपत्तियों की पंजी तैयार करना।
  - परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के लिये आवश्यक विकास कार्य, जिससे परिसंपत्ति का बेहतर प्रबंधन हो सके।
  - शासकीय विभागों एवं उपक्रमों को सेवा शुल्क के आधार पर परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण तथा प्रबंधन के लिये सलाहकारी सेवा प्रदाय करना।
  - आवश्यकतानुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर इसे लोकहित के विभिन्न कार्यों में उपयोग करना।

मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 25 जनवरी, 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिये 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश के 5 व्यक्ति इन पुरस्कारों की सूची में शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मविभूषण', उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मभूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मश्री 'पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

नोट :

- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इत्यादि में प्रदान किये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष 'गणतंत्र दिवस'के अवसर पर की जाती है तथा आमतौर पर मार्च/अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं।
- इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंज़री दी है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार (किसी जोड़ी को दिये पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है) भी शामिल हैं। इस सूची में 4 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है।
- वर्ष 2022 के लिये घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं-
  - भोपाल के स्व. डॉ. नरेंद्र प्रसाद मिश्रा (मरणोपरांत) को चिकित्सा के क्षेत्र में 'पद्मश्री'पुरस्कार के लिये चुना गया है।
  - इसी प्रकार अर्जुन सिंह धुर्वे को कला, अवधकिशोर जड़िया को साहित्य एवं शिक्षा तथा रामसहाय पांडे और सुश्री दुर्गाबाई व्याम को कला के क्षेत्र में 'पद्मश्री'पुरस्कार के लिये चुना गया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिजीशियन स्व. डॉ. नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने भोपाल गैस त्रासदी के बाद हज़ारों पीड़ितों हेतु असाधारण चिकित्सा व्यवस्था के लिये कार्य किया था।
  - डिंडौरी के अर्जुन सिंह धुर्वे ने बैगा नृत्य एवं संस्कृति को प्रवाहमान रखते हुए लोककला को शिखर पर पहुँचाया, वहीं मंडला की सुश्री दुर्गाबाई व्याम ने गोंड लोककथा की चित्रकारी को न केवल प्रवाहमान रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाई।
  - सागर ज़िले के प्रतिभावान कलाकार रामसहाय पांडेय ने बुंदेलखंड के गीत-संगीत संस्कृति की पहचान 'राई नृत्य'को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है।

'मास्क ही है ज़िंदगी' अभियान में 2 लाख 91 हज़ार 631 मास्क वितरित

चर्चा में क्यों ?

- 28 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे 'मास्क ही है ज़िंदगी' अभियान में 28 जनवरी तक 2 लाख 91 हज़ार 631 मास्क ज़रूरतमंदों को वितरित किये जा चुके हैं। यह अभियान 20 जनवरी को सभी नगरीय निकायों में एक साथ शुरू किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- नगरीय निकायों में अभी तक जन-सहयोग से 1724 मास्क बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। इनमें नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा एक लाख 37 हज़ार 761 मास्क दान स्वरूप दिये जा चुके हैं।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि 28 जनवरी को नगरीय निकायों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 44 हज़ार 996 मास्क वितरित किये गए हैं।
- भोपाल संभाग के नगरीय निकायों में 4 हज़ार 853, चंबल में 345, ग्वालियर में 20 हज़ार 41, इंदौर में 3 हज़ार 483, जबलपुर में 2 हज़ार 258, नर्मदापुरम् में 2 हज़ार 276, सागर में 5 हज़ार 521, शहडोल में 142 और उज्जैन संभाग के नगरीय निकायों में 4 हज़ार 80 मास्क वितरित किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। 'रोको-टोको' अभियान में अभी तक 2 लाख 87 हज़ार 790 घरों में संपर्क किया जा चुका है। लगभग 4871 ऑनलाइन चर्चाएँ आयोजित की गई हैं।

नोट :

डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में धारा 44 लागू

चर्चा में क्यों ?

- 28 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू में अनियमितताओं के कारण कुलपति डॉ. आशा शुक्ला को हटाते हुए धारा 44 लागू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. आशा शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें इंदौर संभागायुक्त द्वारा की गई जाँच में सही पाई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- उन पर पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधिवत प्रक्रिया का पालन कर राशि खर्च करने, परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में अनियमितता, बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का गठन करने के संबंध में आरोप लगे थे।
- साथ ही कुलपति पर जाँच के दौरान शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज़ भी जाँच समिति को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है।
- वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शासकीय होल्कर साइंस कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. डी. के. शर्मा को डॉ. बी.आर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इंदौर का नया कुलपति नियुक्त किया है।
- गौरतलब है कि इससे पहले कुलपति डॉ. आशा शुक्ला भोपाल की बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थीं। उस समय भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे।

मध्य प्रदेश में बनेगा भारत का पहला जियो पार्क

चर्चा में क्यों ?

- 29 जनवरी, 2022 को जबलपुर से लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गाँव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। GSI ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये 1.30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
- गौरतलब है कि यह स्थल प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिये यूनेस्को की भू-विरासत की अस्थायी सूची में पहले से मौजूद है।
- नर्मदा घाटी में, विशेषरूप से जबलपुर के भेड़ाघाट-लम्हेटा घाट क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। 1828 ई. में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम स्लीमैन द्वारा लम्हेटा बेड से पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्र किया गया था।
- भेड़ाघाट जो सफेद संगमरमर की चटोनी संरचना के लिए जाना जाता है, में 15.20 करोड़ रुपये की लागत से एक विज्ञान केंद्र भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाएगी।

'बीटिंग द रिट्रीट' के साथ संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह

चर्चा में क्यों ?

- 29 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 'बीटिंग द रिट्रीट' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- 'बीटिंग द रिट्रीट' कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सम्मान प्रकट करने के साथ हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के ब्रास बैंड, मास्ड बैंड, पाइप बैंड और आर्मी बैंड ने सामूहिक वादन की मनोहारी प्रस्तुति दी।

नोट :

- पुलिस ब्रास बैंड द्वारा देशभक्ति, फिल्मी, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय राग और पाश्चात्य क्लासिकल संगीत की मनोहारी धुनें निकाली गईं। इसी कड़ी में हिन्दी फिल्मों के गीतों की सुमधुर संगीतमय प्रस्तुति दी गईं। इसके बाद सभी बैंड द्वारा मार्चपास्ट करते हुए बैंडवार सामूहिक प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- उल्लेखनीय है कि देश में 'बीटिंग द रिट्रीट' कार्यक्रम आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष 29 जनवरी को पुलिस द्वारा राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के विजय चौक पर भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना के बैंड दलों द्वारा वादन एवं मार्चपास्ट की आकर्षक सामूहिक प्रस्तुति राष्ट्रपति के समक्ष की जाती है।
- विदित हो कि 'बीटिंग द रिट्रीट' का आयोजन अर्ध सैन्य बलों की एक सुदीर्घ प्राचीन परंपरा है, जब युद्ध के बाद सैन्य टुकड़ियाँ वापस अपने कैंपों में आती थीं, तब युद्ध के तनाव को कम करने के लिये मनोरंजक बैंड वादन का कार्यक्रम रखा जाता था। भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन होता है।

फरवरी को 'स्वच्छता संकल्प माह' के रूप में मनाया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

- 29 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार फरवरी-2022 को 'स्वच्छता संकल्प माह' के रूप में मनाया जाएगा। 'स्वच्छता संकल्प माह' एक से 28 फरवरी तक आयोजित होगा।

प्रमुख बिंदु

- 'स्वच्छता संकल्प माह' का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 की तैयारी पूरी कर प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाना है।
- मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में प्रत्येक निकाय को ओडीएफ प्रमाणीकरण प्राप्त करने, गार्बेज-फ्री सिटी की स्टार रेटिंग में नगर निगमों को 5-स्टार तथा अन्य नगरीय निकायों को न्यूनतम 3-स्टार प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रेरक दौड़ श्रेणी में सभी निकायों को कम-से-कम गोल्ड/सिल्वर प्राप्त करने के निर्देश भी दिये हैं।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में जिला कलेक्टरों को भी पुरस्कृत किया जाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सभी नगरीय निकायों में 26 जनवरी से 'स्वच्छ प्रतिष्ठान' सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है।
- 'स्वच्छता संकल्प माह-2022' के लिये जारी कैलेंडर में एक से 5 फरवरी तक थीम स्टार रेटिंग, 6 से 10 फरवरी तक ओडीएफ, 11 से 15 फरवरी तक सिटीजन फीडबैक और एंगेजमेंट, 16 से 20 फरवरी तक समस्त अधो-संरचना निर्माण गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इस दौरान 16 से 20 फरवरी तक एफएसटीपी का मटेरियल रिकवरी केंद्रों, कंपोस्टिंग इकाइयों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री द्वारा 21 से 25 फरवरी तक संवाद, समीक्षा एवं अधो-संरचनाओं का लोकार्पण, 25 से 27 फरवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण और 28 फरवरी को समापन गतिविधि की जाएगी। समापन दिवस पर नगरीय निकायों की टीम कचरा संग्रहण वाहनों के साथ नगर में भ्रमण करेगी। यह दिन पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। साथ ही वार्डों में कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों और सहयोगियों को शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा।

नोट :